Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 24-08-2005

Participants : Singh Shri Bijendra

>

Title : Regarding shortage of power in the country.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने विद्युत जैसी अहम समस्या पर मुझे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई का भारी संकट है। 24 घंटों में से 18 घंटे बिजली सप्लाई की घोाणा उद्योगों के लिए है और 14 घंटों के लिए किसानों और ग्रामीण अंचलों में बिजली सप्लाई की घोाणा है, लेकिन ये कोरी घोाणाएं ही साबित हुई हैं। 24 घंटों में से मात्र दो घंटे की ि वद्युत सप्लाई हो रही है। आम जनता विद्युत समस्या से त्रस्त है। हम मानते हैं कि विद्युत समस्या पूरे देश की समस्या है लेकिन उत्तर प्रदेश में ि वद्युत का असमान रूप से वितरण हो रहा है। एटा, मैनपुरी, उन्नाव और इटावा में तो 24 घंटे बिजली की सप्लाई है जबकि जनपद अलीगढ़ में 24 घंटों में से मात्र दो घंटे ही बिजली रहती है। आम जनता धरना-प्रदर्शन कर रही है। विद्यत अधिकारियों के साथ पुलिस ने आम जनता पर लाठीचार्ज किया। 9 अगस्त को हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की धान की रोपाई का वक्त है और इस समय तमाम फसल चौपट हो रही है। अगर विद्युत समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसान को बहुत हानि होगी। इसके साथ-साथ अलीगढ़ में लॉक इंडस्ट्री है और यह एक औद्योगिक नगरी है। विद्युत के अभाव में वहां इंडस्ट्रीज़ चौपट हो गई हैं और बहुत भारी नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 2600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलों का भुगतान अभी बकाया है जिसमें से 1800 करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्र से बकाया हैं, जबकि मात्र 800 करोड़ रुपये किसानों और सामान्य उपभोक्ताओं से बकाया हैं।

यदि सरकार की नीयत सही है तो पहले उद्योगों से बिलों का भुगतान लेना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि रोस्टर के मुताबिक 24 घंटों में से कम से कम 14 घंटे बिजली की सप्लाई ग्रामीण अंचलों में की जाए जिससे वहां के किसानों की समस्या का समाधान हो सके, छात्रों को पढ़ने के लिए बिजली मिल सके और उद्योगों को उत्पादन के लिए समयानुसार बिजली मिल सके। मैं सरकार से चाहूंगा कि उचित निर्देश देकर समस्या का समाधान कराए।

MR. CHAIRMAN: You have asked for a Labour Welfare Office to be opened in the State. You can make a mention of it. Strictly speaking, the issue of opening a Labour Welfare Office falls within the powers of the State Government.